क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 02 अंक: 03, शुक्रवार, 25 जनवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार-समाचार

मैं ऐसे लोगों की नियुक्ति करता हूं जो 4-5 साल बाद मेरे बॉस बन सकें: अलीबाबा के कार्यकारी चैयरमैन जैक मा

दावोस: चीन के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज जैक मा ने बुधवार को कहा कि कोई भी विशेषज्ञ ऐसा नहीं है जो आने वाले कल के बारे में जानता हो, वे सिर्फ बीते कल के बारे में ही जानते हैं. विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए अलीबाबा के कार्यकारी चेयरमैन ने उद्योग जगत के नेताओं से कहा कि उन्हें प्रतिस्पर्धा और दबाव को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, ''यदि आप दबाव को लेकर चिंतित होते हैं तो आप उद्यम क्षेत्र में न आएं. आज सबसे अच्छी बात यह है कि हर कोई हर चीज को लेकर चिंतित है.''

जैक मा ने सवालों के दिए ऐसे जवाब

यह पूछे जाने पर पिछले 20 साल के दौरान अलीबाबा को आगे बढ़ाते समय क्या उन्हें कभी डर लगा है या संदेह हुआ है, मा ने कहा कि आने वाले कल का विशेषज्ञ कोई नहीं होता है, सब बीते कल के विशेषज्ञ हैं.

25 खरब रुपए के मालिक जैक मा करेंगे फिल्मों में काम, ये है वजह

पॉजिटिव लोग हैं जैक मा की पसंद

यह पूछे जाने पर कि वह अपनी कंपनी में कैसे लोगों की नियुक्ति करते हैं, मा ने कहा, ''जब किसी की नियुक्ति करता हूं तो यह देखता हूं कि वह मेरे से स्मार्ट हो. वे ऐसे लोग हों जो चार या पांच साल बाद मेरे बॉस बन सकें. मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो सकारात्मक हों और जो कभी हार नहीं मानते हों.''

TCS दुनिया का तीसरी सबसे बहु-मूल्य आईटी सेवा प्रदाता ब्रांड बना

नयी दिल्ली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को 2018-19 में दुनिया का तीसरी सबसे बहुमूल्य आईटी सेवा ब्रांड रैंकिंग दी गई है। पहले पायदान पर एसेंचर और दूसरे पर आईबीएम है। ब्रांड फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। दुनिया की शीर्ष दस कंपनियों में भारत की चार आईटी सेवा प्रदाता कंपनियां हैं। इनमें टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल और विप्रो शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की सबसे बहुमूल्य आईटी सेवा ब्रांड एसेंचर है। उसकी ब्रांड मूल्य 26.3 अरब डॉलर है। इससे पहले आईबीएम सबसे बहुमूल्य कंपनी थी। आईबीएम 20.4 अरब डॉलर के साथ दूसरे पायदान पर आ गई है।

NCD धारकों को 375 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर पाएगी आरकॉम

मुंबई। कर्ज के बोझ से दबी दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने बुधवार को कहा कि वह गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों की मूल राशि पर 375 करोड़ रुपये की चौथी किस्त का भुगतान नहीं कर पाएगी। कंपनी को यह भुगतान सात फरवरी को करना है।शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा है कि वह संपत्ति बिक्री की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की प्रक्रिया में है। संपत्ति बिक्री मार्च, 2019 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है।अनिल अंबानी की कंपनी ने कहा कि वह पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने तथा एनसीडी की मूल्य राशि पर 375 करोड़ रुपये की चौथी किस्त का भुगतान नहीं कर पाएगी।

ऑरेकल पर लगा भारतीयों से भेदभाव करने का आरोप, अंग्रेजों के मुकाबले दिया 25 फीसद कम वेतन

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अमेरिका के श्रम विभाग ने अमेरिकी कंपनी ऑरेकल पर भारतीयों, एशियन और अफ्रीकन अमेरिकन कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। विभाग ने आरोप लगाया है कि कंपनी में गोरे और गैर एशियाई कर्मचारियों की तुलना में भारतीयों को समान पदों पर होते हुए भी 25 फीसद कम वेतन दिया गया है। यह खबर एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई है।वहीं दूसरी तरफ ऑरेकल ने प्रॉडक्ट डिवेलपर के पद पर एशियाई देशों में सबसे ज्यादा नौकरियां भारतीय कर्मचारियों को ही दी हैं। हालांकि अमेरिका में यह कंपनी गोरों को समान पदों पर जो वेतन दे रही है उतना ही वेतन भारतीयों, अफ्रीकियों और अन्य लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अमेरिका के श्रम विभाग ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंपनी गैर-एशियाई आवेदकों को रोजगार के समान अवसर नहीं देती है और ऐसे लोगों को ज्यादा तरजीह देती है जिनसे बाद में कम सैलरी पर भी काम कराया जा सके।यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के फेडरल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस प्रोग्राम्स ऑफिस ने अपनी शिकायत में कहा, जब बात रोजगार की होती है तो कंपनी में महिलाओं, काले एवं एशियाई कर्मचारियों को भी उनके गोरे साथियों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है।

ऑरेकल के खिलाफ यह शिकायत अमेरिका में दर्ज हुई है और अमेरिका के श्रम विभाग ने कंपनी पर यह आरोप कंपनी के रेडवुड शोर्स स्थित मुख्यालय में जांच के आधार पर लगाया है। गौरतलब है कि ऑरेकल भारत में डिवलपमेंट सेंटर खोलने वाली शुरुआती दौर की अमेरिकी कंपनियों में एक है।

सरकार सिंगल ब्रैंड खुदरा कंपनियों को स्थानीय खरीद नियमों में दे सकती है छूट

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सिंगल ब्रैंड रिटेल सेक्टर में बड़े विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार अनिवार्य रूप से 30 फीसद सामान की स्थानीय खरीद से जुड़े नियमों में कुछ ढील देने पर विचार कर रही है। इन कंपनियों को नियमनों का पालन करने के लिए अधिक समय दिया जा सकता है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है।

बड़ी सिंगल ब्रैंड रिटेल कंपनियों को दुकानें स्थापित करने से पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की इजाजत दी जा सकती है। वर्तमान में सिंगल ब्रैंड रिटेल कंपनियों को ऑनलाइन बिक्री की इजाजत आउटलेट खोलने के बाद ही दी जाती है। सरकार जिस प्रस्ताव पर विचार कर रही है उसके मुताबिक सिंगल ब्रैंड फॉरेन रिटेलर्स को बिजनेस के शुरुआती 10 वर्षों के लिए भारत से सामानों की खरीद को अपने हिसाब से घटाने और बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है जो कि वर्तमान में पांच वर्ष की है। अभी भारत से 30 फीसद सामानों की खरीद की अनिवार्यता लागू है।हालांकि यह छूट कुछ शर्तों से साथ दी जाएगी। शर्त के मुताबकि ऐसी कंपनियों को दो से तीन वर्षों के भीतर 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश भारत में लाना ही होगा। इस कदम के पीछे का मकसद सेक्टर में बड़े निवेशकों को आकर्षित करना है। हालांकि इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी।गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2018 में इस सेक्टर में 100 फीसद एफडीआई की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही सिंगल ब्रैंड रिटेल से जुड़ी विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई थी।

नहीं बदले सोने के दाम, जानिए आज कितनी सस्ती हो गई चांदी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सोने की कीमतें आज 33,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर स्थिर रही हैं। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार के कारोबार में सुस्त खरीदारी के कारण सोना स्थिर रहा है।सोने के उलट चांदी की कीमतें आज के कारोबार में कम हुई हैं। गुरुवार के कारोबार में चांदी 210 रुपये की गिरावट के साथ 39,950 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई है। ट्रेडर्स का कहना है कि घरेलू हाजिर बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह औद्योगिक इकाईयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से कमजोर उठान रही है।

वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.09 फीसद की गिरावट के साथ 1,282.10 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.33 फीसद की गिरावट के साथ 15.33 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बंद हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी 210 रुपये की गिरावट के साथ 39,950 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई है। वहीं साप्ताहिक आधारित डिलीवरी 993 रुपये गिरकर 38,994 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है।हालांकि चांदी के सिक्कों का भाव 77,000 रुपये लिवाल और 78,000 रुपये प्रति 100 पीस बिकवाल पर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 99.9 फीसद और 99.5 फीसद शुद्धता वाला सोना क्रमश=33,210 और 33,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा है। सोने की कीमतों में बुधवार को 115 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि गिन्नी के भाव 25,500 रुपये प्रति 8 ग्राम पीस पर बरकरार रहे हैं।

चंदा कोचर मामले में CBI ने दर्ज की एफआईआर, वीडियोकॉन के मुख्यालयों पर छापेमारी

नई दिल्ली : दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं में शामिल रहीं आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस मामले में दिल्ली और मुंबई समेत 4 जगहों पर जांच एजेंसी की रेड चल रही है. सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर से जुड़े ऋण मामले में मुंबई, औरंगाबाद में वीडियोकॉन ग्रुप के मुख्यालयों पर छापेमारी की है. सीबीआई को उम्मीद है कि छापेमारी में कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते हैं.

वीडियोकॉन को लोन देने में अनियमितता के आरोपआपको बता दें कि चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन को लेकर आरोप लगे थे. कोचर पर आरोप लगा कि उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने के दौरान अनियमितता बरती और अवैध तरीके से निजी लाभ लिया. इसमें चंदा कोचर के पति दीपक कोचर का नाम भी सामने आया था.

वीडियोकॉन लोन मामले में घिरने के बाद चंदा कोचर ने अक्टूबर में आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था. कोचर ने आईसीआईसीआई ग्रुप की सभी सब्सिडियरी से भी इस्तीफा दे दिया था. चंदा कोचर के इस्तीफे के बाद बैंक की तरफ से संदीप बख्शी को 5 साल के लिए आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था.

सरकार की 2022 तक e-NAM मंच से 22,000 मंडियों को जोड़ने की योजना

मुंबई। केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार देश भर के साप्ताहिक और सप्ताह में दो बार लगने वाले अस्थायी बाजारों सहित सभी 7,500 कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) को वर्ष 2021-22 तक कृषि जिंसों के केन्द्रीकृत आनलाइन उपभोक्ता जिंस व्यापारिक मंच (ई-नाम) के साथ जोड़ने की योजना बना रही है। मंत्री ने यहां 'क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया' द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि पहले से ही देश की 585 मंडियों को ई-नाम के साथ जोड़ा जा चुका है और वित्तवर्ष 2020 तक हम इसके साथ देश भर में 400 अन्य मंडियों को जोड़ देंगे।इसके बाद आनलाइन एपीएमसी की कुल संख्या 1,000 हो जायेगी। इसके अलावा देश भर में कृषि एवं गैर-कृषि जिंसों में कारोबार करने वाली करीब 14,500 तात्कालिक या अस्थायी मंडियां हैं जिन्हें कृषि मंत्रालय ई-नाम के साथ जोड़ना चाहती है। सम्मेलन

में उन्होंने कहा, ''पहले से ही 585 मंडियां ई-नाम से सम्बद्ध हैं और हम वर्ष 2022 तक 22,000 मंडियों को इससे जोड़ने की योजना बना रहे हैं।''सिंह ने कहा, यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को विकसित करने और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा, उत्पादन लागत कम करने, किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, अपव्यय रोकने और आय के वैकल्पिक स्रोतों को सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को निर्णायक तरीके से देखा जा रहा है।मंत्री ने कहा कि अगर सरकार, उद्योग और किसान एक साथ काम करें तो कई चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, सरकार उद्योग के साथ काम कर रही है ताकि किसानों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके। हालांकि, समर्थन की गति में तेजी लाने की जरूरत है। सिंह ने कहा, देश में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए योजनायें बनाने और लागू करने के लिए 2014 से 19 के बीच कृषि मंत्रालय का बजट आवंटन 2,11,694 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

बजट 2019 में मोदी सरकार नौकरीपेशा लोगों को दे सकती है यह सबसे बड़ा तोहफा

नई दिल्ली : मोदी सरकार की तरफ से आगामी 1 फरवरी को साल 2019 का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा. इस बार चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट से किसानों के साथ ही नौकरीपेशा और कारोबारी वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं. लेकिन इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद नौकरीपेशा लोगों को है. बजट भाषण से पहले और बजट भाषण के दौरान पूरे समय सबकी सबके निगाहें नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत पर होगी. इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद नौकरीपेशा लोगों को है. नौकरी करने वालों को आयकर छूट सीमा बढ़कर 5 लाख रुपये होने की उम्मीद है. इसके अलावा बजट में कृषि क्षेत्र पर भी खास ध्यान रहेगा.

स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाने का विकल्प

बजट विशेषज्ञों को भी उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा की मौजूदा छूट को बढ़ाकर सरकार 5 लाख रुपये तक कर सकती है. यह घोषणा हुई तो इसका सबसे ज्यादा फायदा नौकरी पेशा लोगों को होगा. इसके अलावा मेडिकल और कन्वेंस को भी फिर से लागू करने की उम्मीद की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक एक विकल्प ये भी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजारी रुपये सालाना से बढ़ाकर कुछ और कर दिया जाए.

फिलहाल क्या व्यवस्था ?

वर्तमान में, 2.5 लाख रुपए की आय को टैक्स में छूट मिलती है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि 5-10 लाख रुपए की सालाना आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है. जबकि 80 साल के अधिक की उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपए सालाना की आय पर टैक्स में छूट मिलती है.

80ष्ट के तहत छूट बढ़कर हो 3 लाख रु

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने व्यक्तिगत इनकम टैक्सपेयर्स को निवेश योजनाओं में के आधार पर धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ा कर 3 लाख रुपए करने की भी सिफारिश की है.

गुजरात में EWS कोटे के लिए सिर्फ 8 लाख रुपये की आय सीमा पर्याप्त

यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितनी कृषि योग्य भूमि या कितना बड़ा घर है।

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने बुधवार को कहा कि वह सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केवल आठ लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को ही इसके मानदंड के अंतर्गत सम्मिलित करेगी और भूमि और घर के मालिकाना हक के शर्तों को इसमें नहीं रखा जाएगा।यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है।

यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितनी कृषि योग्य भूमि या कितना बड़ा घर है।

सरकार एकल- ब्रांड खुदरा कंपनियों को स्थानीय खरीद नियमों में देगी छूट !

नयी दिल्ली। एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में बड़ी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार अनिवार्य रूप से 30 प्रतिशत सामान की स्थानीय खरीद से जुड़े नियमों में कुछ राहत देने पर विचार रही है।

सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन कंपनियों को नियमनों के अनुपालन के अधिक समय दिया जा सकता है।बड़ी एकल खुदरा कंपनियों को दुकानें स्थापित करने से पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में एकल-ब्रांड खुदरा कंपनी को ऑनलाइन बिक्री की अनुमति केवल भौतिक रूप से आउटलेट खोलने के बाद ही दी जाती है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार द्वारा विचाराधीन प्रस्ताव के मुताबिक, एकल ब्रांड रिटेल कारोबार के लिए 30 प्रतिशत भारत से खरीद करने के नियम को लचीला बनाया जा सकता है।

संपादकीय

तू-तू-मैं-मैं

ईवीएम को लेकर जारी तू-तू-मैं-मैं निस्संदेह, ह्रदयविदारक है। हमारे नेतागण संकीर्ण राजनीतिक सोच के तहत हर संस्था और व्यवस्था पर जिस तरह चोट कर रहे हैं; उनका अंत कहां जाकर होगा, कहना कठिन है। एक हैकर, जिसका चेहरा तक हमारे सामने नहीं, वह अमेरिका में बैठने का दावा करता हुआ लंदन के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाता है कि 2014 के आम चुनाव में व्यापक पैमाने पर ईवीएम की हैकिंग हुई थी और उसे सच मानकर भारत में राजनीतिक मोर्चाबंदी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह हैकर न होकर ऐसा विश्वसनीय प्राणी है जिसके मुख से केवल सत्य बाहर निकला हो। उसके सामने हमारा चुनाव आयोग गलत, सर्वोच्च न्यायालय गलत, विशेषज्ञ गलत। वह तो यह भी कह रहा है कि भारत की कई पार्टियों ने चुनाव के दौरान उससे संपर्क किया था। क्या हंगामा करने वाली पार्टियां एवं उनके नेतागण ईवीएम हैक करने के लिए उससे संपर्क किया था? क्या वे उसके इस आरोप से सहमत हैं? कोई यह सोचने को तैयार ही नहीं है कि कहीं उस व्यक्ति के पीछे कुछ भारत विरोधी शक्तियां तो नहीं जो इस तरह राजनीतिक विभाजन का लाभ उठाकर टकराव पैदा करना चाहती हों। आखिर आम चुनाव के ठीक पूर्व ऐसे आयोजन और उसमें लगाए गए आरोपों का उद्देश्य क्या हो सकता है। चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर एकदम सही कदम उठाया है। उसे पकड़कर भारत लाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। अगर पुलिस टालमटोल करे तो आयोग को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। आखिर ईवीएम को संदेहास्पद बनाने का अर्थ चुनाव आयोग को संदेहास्पद बनाना है। ईवीएम में गड़बड़ी बगैर चुनाव आयोग की व्यापक संलिप्तता के संभव नहीं। जब चुनाव आयोग बार-बार ईवीएम को हर दृष्टि से विश्वसनीय होने का बयान दे रहा है, देश को आाश्त कर रहा है तो इस तरह हंगामों का मतलब क्या निकाला जाए? सर्वोच्च न्यायालय भी चुनाव आयोग को सही कह चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक लड़ाई में ईवीएम और उसके नाते चुनाव आयोग को घसीट रहे हैं। जिन लोगों ने लंदन में कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उनके खिलाफभी जांच होनी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को कानून के कठघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की कार्यपग्राली को शंका के घेरे में लाने का अमर्यादित खेल चलता रहेगा।

पद की शपथ

2014 में लोक सभा का चुनाव जीतने के बाद नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले देश को स्वच्छ बनाने की बात वाराणसी में की थी। उस समय किसी ने यह सोचा नहीं था कि यह अगले कुछ सालों में ही जन आंदोलन का रूप ले लेगा। अब उसी वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन में यह कहते हैं कि देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, तो यह अकारण नहीं है। स्वच्छता अभियान तो देश में पहले भी चल रहा था,लेकिन उसमें जन भागीदारी व्यापक पैमाने पर नहीं थी। अगर इसमें जन भागीदारी बढ़ी, तो यह नेतृत्व की कुशलता के कारण ही हो संभव सकी,अन्यथा देश की मिट्टी और लोग तो वही थे। नेता का कार्य केवल सड़क-पुल बनाना ही नहीं होता,बल्कि राष्ट्र का निर्माण करना होता है, उसे एक दिशा देनी होती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के काम का मूल्यांकन करना हो, तो उसे केवल विकास के पैमाने पर नहीं आंका जा सकता, उसका सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। सड़क-पुल तो कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्र-समाज की अस्मिता ही नष्ट हो गई तो फिर उसे पुनर्स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। मोदी सरकार ने न केवल विकास की कार्य-संस्कृति बदलने, बल्कि देश के भीतर और बाहर भारतीय परंपरा और संस्कृति को प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी किया है। एक भारतीय को अपनी सभ्यता-संस्कृति पर गर्व करने का मौका प्रदान किया है। वह लीक से हटकर सवाल कर रहा है।

आज का भारत औपनिवेशिक दासता के चिह्नों को उखाड़ फेंकना चाहता है। अपनी जड़ों से जुड़ने-जोड़ने की सोच का ही परिणाम है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन अबकी बार ऐसे समय में किया गया, जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतवंशियों को भी इसका अहसास होने से बाकी नहीं रहा। तभी तो मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीन्द्र जगन्नाथ यह कहने से अपने को नहीं रोक सके कि भारत अतुल्य है और भारतीयता सार्वभौम। बेशक इसमें वैश्वीकरण की प्रवृत्ति का भी योगदान है, जो दुनिया के विभिन्न देशों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित कर रही है। पर इसको नकारा नहीं जा सकता कि भारत बदल रहा है।

सत्संग

ईश्वर

ईश्वर का दंड एवं उपहार दोनों ही असाधारण हैं। इसलिए आस्तिक को इस बात का सदा ध्यान रहेगा कि दंड से बचा जाए और उपहार प्राप्त किया जाए। यह प्रयोजन छिट-पुट पूजा-अर्चना, जप-ध्यान से पूरा नहीं हो सकता। भावनाओं और क्रियाओं को उत्कृष्टता के ढांचे में ढालने से ही यह प्रयोजन पूरा होता है। न्यायनिष्ठ जज की तरह ईर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। स्तवन अर्चन करके उसे उसके नियम विधान से विचलित नहीं किया जा सकता है। अपना गुणगान करने वाले के साथ यदि वह पक्षपात करने लगे, तब उसकी न्याय व्यवस्था का कोई मूल्य न रहेगा, सृष्टि की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। सबको अनुशासन में रखने वाला परमेश्वर स्वयं भी नियम व्यवस्था में बंधा है। यदि कुछ उच्छृंखलता एवं अव्यवस्था बरतेगा तो फिर उसकी सृष्टि में पूरी तरह अंधेरा फैल जाएगा। फिर कोई उसे न तो न्यायकारी कहेगा और न समदर्शी। तब उसे खुशामदी या रिश्वतखोर नाम से पुकारा जाने लगेगा, जो चापलूस स्तुति सा कर पुष्प-नैवेद्य भेंट कर दें, उससे प्रसन्न। भगवान् को हम सर्वव्यापक एवं न्यायकारी समझकर गुप्त या प्रकट रूप से अनीति अपनाने का कभी भी, कहीं भी साहस न करें। ईर के दंड से डरें। उसका भक्त वत्सल ही नहीं, भयानक रौद्र रूप भी है। उसका रौद्र रूप ईरीय दंड से दंडित असंख्यों रुग्ण, आसक्त, मूक, वधिर, अंध, अपंग, कारावास एवं अस्पतालों में पड़े हुए कष्टों से कराहते हुए लोगों की दयनीय दशा को देखकर सहज ही समझा जा सकता है। केवल वंशी बजाने वाले और रास रचाने वाले ईर का ही ध्यान न रखें, उसका त्रिशूलधारी भी एक रूप है, जो असुरता में निमग्न दुरात्माओं का नृशंस दमन, मर्दन भी करता है। न्यायनिष्ठ जज को जिस प्रकार अपने सगे-संबंधियों, प्रशंसक मित्रों तक को कठोर दंड देना पड़ता है, फांसी एवं कोड़े लगाने की सजा देने को विवश होना पड़ता है, वैसे ही ईर को भी अपने भक्त-अभक्त का, प्रशंसक-निंदक का भेद किए बिना उसके शुभ-अशुभ कर्मो का दंड पुरस्कार देना होता है। ईर हमारे साथ पक्षपात करेगा, सत्कर्म न करते हुए भी विविध सफलताएं देगा या दुष्कर्म करते रहने पर भी दंड से बचे रहने की व्यवस्था कर देगा, ऐसा सोचना नितांत भूल है। उपासना का उद्देश्य पल्रोभन के अवसर आने पर भी सत्पथ से विचलित न होने की दृढ़ता प्रदान करे यही ईर की कृपा का सर्वश्रेष्ठ चिह्न है।

अंतरिम बजट

वर्ष 2009 में जब प्रणव मुखर्जी ने वित्तमंत्री के रूप में अंतरिम बजट पेश किया तब अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर 2008 में उभरी नियंतण्र आर्थिक मंदी के असर की चिंताएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। प्रणव मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने अंतरिम बजट भाषण में राजकोषीय लक्ष्य पर खरा उतरने में सरकार की नाकामी को रेखांकित किया था। फिर वर्ष 2014 में पी. चिदंबरम ने जब अंतरिम बजट पेश किया था तो अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं थी, नियंतण्र बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे और राजकोषीय घाटा चिंताजनक स्थिति में था। ऐसे में पी. चिदंबरम ने जहां आर्थिक दिशाएं प्रस्तुत कीं, वहीं उन्होंने पूंजीगत उत्पादों, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों, कारों, दोपहिया वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों सहित कई उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटा दिए। कई घरेलू उत्पादों के संरक्षण हेतु उत्पाद शुल्क की नई दरें भी घोषित कीं। केवल एक बार 2009 के अंतरिम बजट में प्रणव मुखर्जी ने नए कर प्रस्तावों से पूरी तरह दूरी बनाए रखी थी, जबकि जसवंत सिंह और चिदंबरम ने कराधान प्रस्ताव और विभिन्न वर्गों के लिए राहतकारी प्रावधान भी जोर-शोर से प्रस्तुत किए थे। नया अंतरिम बजट प्रमुखतया खेती और

सतीश पेडणोकर

देश की निगाहें नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा 1 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट की ओर लगी हुई है। वित्तमंत्री अरु ण जेटली ने कहा है कि मोदी सरकार 1 फरवरी को आगामी वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में सिर्फतीन महीने के लिए लेखानुदान ही पेश नहीं करेगी, वरन देश की कुछ आर्थिक-सामाजिक चुनौतियों के समाधान हेतु अर्थव्यवस्था के हित को भी ध्यान में रखते हुए बजट के माध्यम से नीतिगत दिशाएं भी प्रस्तुत करेगी। वित्तमंत्री ने आम आदमी, किसानों, छोटे उद्यमियों कारोबारियों, मध्यम वर्ग और छोटे आयकरदाताओं के लिए राहत के स्पष्ट संकेत भी दिए हैं। चूंकि 2019-20 का अंतरिम बजट आम चुनाव के पहले का आखिरी बजट होगा, अतएव इसे लोक लुभावन बनाए जाने की संभावनाएं हैं। आजादी के बाद से अब तक तीन अंतरिम बजट प्रस्तुत किए गये हैं। चौथा अंतरिम बजट मोदी सरकार द्वारा आगामी एक फरवरी को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया जाएगा। इसके पूर्व में वर्ष 2004 में वाजपेयी सरकार के समय जसवंत सिंह ने तथा मनमोहन सिंह सरकार के समय 2009 में प्रणव मुखर्जी ने और 2014 में पी चिदंबरम ने अंतरिम बजट पेश किए थे। इन तीनों वित्तमंत्रियों के समक्ष परिस्थितियां अलग-अलग थीं।

वर्ष 2004 में जब जसवंत सिंह ने अंतिरम बजट पेश किया, तब अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता दिखाई दे रही थी। जसवंत सिंह ने अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में नई रियायतों के प्रस्ताव रखे थे। वर्ष 2009 में जब प्रणव मुखर्जी ने वित्तमंत्री के रूप में अंतरिम बजट पेश किया तब अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर 2008 में उभरी नियंतण्र आर्थिक मंदी के असर की चिंताएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। प्रणव मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने अंतरिम बजट भाषण में राजकोषीय लक्ष्य पर खरा उतरने में सरकार की नाकामी को रेखांकित किया था। फिर वर्ष 2014 में पी. चिदंबरम ने जब अंतरिम बजट पेश किया था तो अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं थी, नियंतण्र बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे और राजकोषीय घाटा चिंताजनक स्थिति में था। ऐसे में पी. चिदंबरम ने जहां आर्थिक दिशाएं प्रस्तुत कीं, वहीं उन्होंने पूंजीगत उत्पादों, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों, कारों, दोपहिया वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों सहित कई उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटा दिए। कई घरेलू उत्पादों के संरक्षण हेतु उत्पाद शुल्क की नई दरें भी घोषित कीं। केवल एक बार 2009 के अंतरिम बजट में प्रणव मुखर्जी ने नए कर प्रस्तावों से पूरी तरह दूरी बनाए रखी थी, जबकि जसवंत सिंह और चिदंबरम ने कराधान प्रस्ताव और विभिन्न वर्गों के लिए राहतकारी प्रावधान भी जोर-शोर से प्रस्तुत किए थे। नया अंतरिम बजट प्रमुखतया खेती और किसानों को लाभान्वित करते हुए दिखाई दे सकता है। सरकार इस बजट में नकद के रूप में राहत देने के लिए ऐसी योजना प्रस्तुत कर सकती है जिसके तहत किसानों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए सब्सिडी की जगह सीधे उनके खातों में नकद रकम ट्रांसफर की जाएगी। सरकार खेती-बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की सब्सिडी को जोड़ने की एक उपयुक्त योजना प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें करीब 70 हजार करोड़ रु पये चाहिए होगा। कृषि कर्ज का लक्ष्य 10 फीसद बढ़ाकर करीब 12 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। छोटे आयकरदाता नौकरी पेशा वर्ग के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लोग भी चाहते हैं कि उन्हें नए बजट में आयकर राहत मिले, ऐसे में सरकार के द्वारा नए वर्ष के अंतरिम बजट में आयकर छूट की सीमा को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 2.50 लाख रु पये है तथा 40 हजार रुपये का स्टैंर्डड डिक्शन सुनिश्चित है। आयकर छूट की सीमा को दोगुनी करके पांच लाख रुपये तक किया जा सकता है। इसके साथ ही आयकर की विभिन्न स्लैबों के तहत भी राहत दी जा सकती है। अभी ढाई लाख से पांच लाख रु.की आय पर पांच फीसद कर लगता है। वहीं 5 से 10 लाख रुपये की आय पर 20 फीसद तथा 10 लाख रु पये से अधिक की आय पर 30 फीसद आयकर लगता है। अब पांच से 10 लाख रु पये तक की आमदनी पर कर की दर घटाकर 10 फीसद और 10 से 20 लाख रुपये की आय पर 20 तथा 20 लाख रुपये से अधिक की आय पर 25 फीसद आयकर लगाया जा सकता है। सीनियर सिटिजन एवं महिला वर्ग के लिए आयकर में छूट की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही बचत को प्रोत्साहन देने के लिए धारा 80सी के तहत कटौती की सीमा बढ़ाकर 2.50 लाख रु .की जा सकती है। इसके अलावा, चिकित्सा खर्च और परिवहन भत्ते पर भी आयकर छूट मिल सकती है। बजट में छोटी-बड़ी हर प्रकार की कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर घटाकर 25 फीसद रखी जा सकती है। इससे कारोबार बढ़ेगा और कर संग्रह भी। बजट में रियल एस्टेट को प्रोत्साहन दिखाई दे सकता है। यदि इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिलता है तो इससे जुड़े अन्य उद्योगों को भी तेजी मिलेगी। इससे कम दर पर फंडिंग हासिल करने में भी मदद मिलेगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर टैक्स में छूट दी जा सकती है। स्टार्टअप्स के लिए एंजेल टैक्स खत्म करने और ई-केवाईसी में ढील दे सकती है। एंजेल टैक्स के कारण स्टार्टअप्स में निवेश बाधित हो रहा है। नए अंतरिम बजट में स्वास्य, शिक्षा छोटे उद्योग-कारोबार और कौशल विकास जैसे विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। निर्यातकों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष इंसेटिव दिया जा सकता है। सालाना पांच करोड़ रु पये तक बिजनेस वाली कंपनियों को कर्ज पर ब्याज में 2 फीसद तक छूट तय की जा सकती है। हम आशा करें कि वर्ष 2019-20 के नए अंतरिम बजट में सरकार एक ओर विभिन्न वर्गों की आर्थिक अपेक्षाओं और उद्योग कारोबार के लिए उपयुक्त रियायतें एवं प्रोत्साहन देती हुई दिखेगी, वहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के ऐसे कदम उठाते हुए भी दिखाई देगी, जिससे वर्ष 2019 के अंत तक भारत नियंतण्र अध्ययन रिपोर्टों को साकार करते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए।

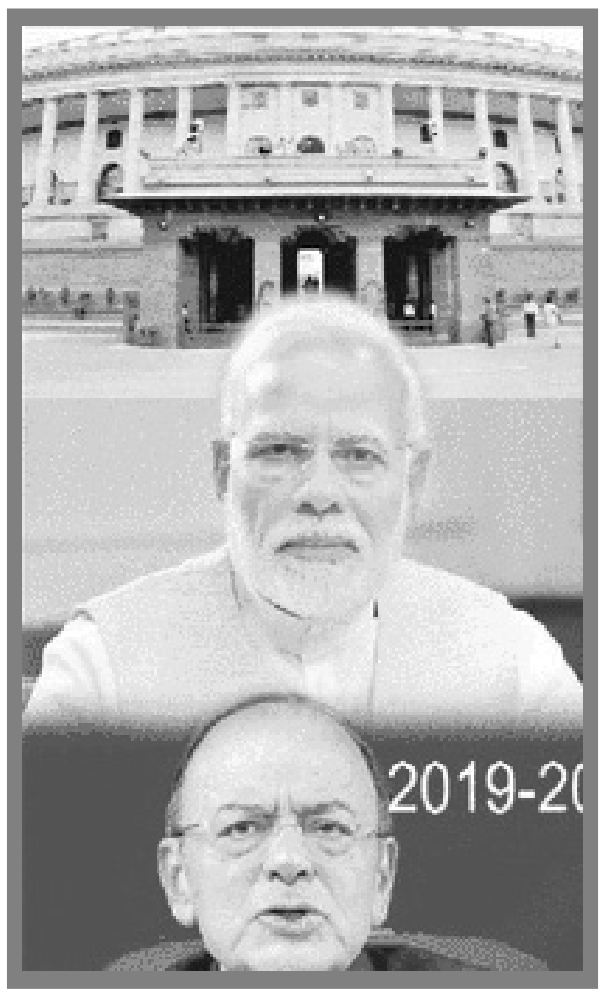

चलते चलते

तख्तापलट के साइड इफेक्ट

देखिए, सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के ही साइड इफेक्ट नहीं होते, जैसा कि अक्सर माना जाता है। सीबीआई के तख्तापलट के साइड इफेक्ट सबसे ताजा मामला है। जी, सीबीआई में मची उथल-पुथल को लोगों ने अब तख्तापलट का ही नाम दिया है, क्या करें! अब तो उनके मुताबिक वहां दो बार तख्तापलट हो चुका। वैसे भी आजकल नाम देने की हवा भी खूब चल रही है। यह शहरों, स्थानों के नए नामकरण की हवा से अलग हवा है। हवा कई तरह की होती है, यह दिल्लीवाले अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन हवा की क्वालिटी अच्छी तो दूसरे दिन उतनी ही खराब। खुद इसमें हवा चलने की काफी भूमिका होती है।अब जो भी हो, पर सीबीआई के तख्तापलट के साइड इफेक्ट खूब हो रहे हैं। अब देखिए जस्टिस सीकरी को एक

सीबीआई के तख्तापलट के साइड इफेक्ट सबसे ताजा मामला है। जी, सीबीआई में मची उथल-पुथल को लोगों ने अब तख्तापलट का ही नाम दिया है, क्या करें! अब तो उनके मुताबिक वहां दो बार तख्तापलट हो चुका। वैसे भी आजकल नाम देने की हवा भी खूब चल रही है। यह शहरों, स्थानों के नए नामकरण की हवा से अलग हवा है। हवा कई तरह की होती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की नियुक्ति मिल रही थी। लेकिन उन्हें छोड़नी पड़ी क्योंकि लोगों ने कुछ इस अंदाज में बातें करनी शुरू कर दी थी कि अच्छा इसीलिए आलोक वर्मा को हटाने के लिए प्रधानमंत्री का साथ दिया था! उन्हें यह सुनना गवारा नहीं हुआ और उन्होंने इस नियुक्ति से अपना नाम वापस ले लिया। इस तख्तापलट का यह पहला साइड इफेक्ट था। फिर सीवीसी चौधरी के इस्तीफे की मांग हो गयी। बोले-यह तो राकेश अस्थाना के केस वापस करवाने के लिए आलोक वर्मा के घर गया था। यह तो स्वतंत्र हैसियत से काम करने की बजाय सरकार के दूत की तरह काम कर रहा था, तो इसे सीवीसी बने रहने का क्या हक है। इस्तीफा दो! यह तख्तापलट का दूसरा साइड इफेक्ट था। इसके बाद खुद राकेश अस्थाना को भी सीबीआई से हटाना पड़ा। कहां तो उन्हें सीबीआई का डारेक्टर बनना था। इसके लिए वे आलोक वर्मा से लड़े भी। फिर भी साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि उनका तबादला करना पड़ा कि भैया जाकर देखो कि हवाई जहाज सुरक्षित उड़ रहे हैं कि नहीं। यह तीसरा साइड इफेक्ट था। वैसे एक साइड इफेक्ट यह भी हुआ कि जस्टिस पटनायक ने कह दिया कि आलोक वर्मा के खिलाफभ्रष्टाचार का तो केस ही नहीं बनता। जबकि उन्हें हटाने का सारा फैसला इसी पर टिका था। अब इसका आगे क्या साइड इफेक्ट होगा, पता नहीं।

फोटोग्राफी...

किन्नर साधु से आशीर्वाद प्राप्त करते श्रद्धालु।

सुभाष चन्द्र बोस

मायावती को लेकर की गयी अनर्गल टिप्पणी आहत करने वाली है। भाजपा नेता सविता सिंह ने अपने स्त्री होने के मान को तो खोया ही, जो वास्तव में न नर हैं, न नारी, उनकी भी तौहीन की। नारि ना मोहे नारि के रूपा, को चरित्रार्थ करने वाली सविता की दोयम दज्रे की टिप्पणी पर विवाद भी हुआ। राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। सच यही है कि औरतों को पुरुषवादी नजरिये से देखने से स्त्री भी मुक्त नहीं है। स्त्री की देहयष्टि को लेकर तय पैमाने पुरुषों की देन हैं। पुरु षों द्वारा स्त्री सौन्दर्य के प्रतिमान खूब रस ले-लेकर स्थापित किये गये हैं। स्वयं स्त्रियों के दिमाग में यह गहरे बिठाया गया है कि उन्हें खूबसूरत नजर आना है। यह विचार किये बगैर कि वे सुन्दर नजर आने को क्यों लालायित हैं? वह अपनी-अपनी आर्थिक हैसियत के अनुरूप बनती-संवरती रहती हैं। वाकई पुरुषों की नजर में उसे खूबसूरत दिखना है या वे अन्य स्त्रियों की बनिस्बत अधिक आकर्षक लगने को लालायित रहती हैं। पारंपरिक रूप से इन तय पैमानों में खुद को साबित करने को वह बेताब रहती हैं। सुन्दर बनने या आकर्षक नजर आने के अपने इस लोभ के पीछे की मंशा पर वह स्वयं कभी विचार नहीं करना चाहतीं। बात फलों की हो, फूलों या अनाज की। विविधताओं के मूल कारण जैविक होते हैं। लेकिन जब बात स्त्री की आती है तो विविधताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। खासकर जब बात अपने देश की हो तो यह मानसिकता रुग्णता में तब्दील हो जाती है। सौन्दर्य के प्रतिमान किसने और कब गढ़े, यह कहना मुश्किल है। सामाजिक, नैतिक व पारिवारिक दबावों ने उसे कभी गहरे सोचने का मौका भी नहीं दिया। अनायास ही उसने खुद को प्रस्तुतिकरण की चीज ज्यादा मान लिया। अमूमन औरतें बनाव-श्रृंगार को आत्मसंतुष्टि से जोड़ने की भूल कर बैठती हैं। वे त्वचा को गोरा करने या झुर्रियां छिपाने वाली क्रीमें लगाएं या बालों को तरह-तरह के रंगों से रंगें। भड़कीले रंगों से होंठों को आकार दें या गालों का गुलाबीपन बढ़ाएं, इसके पीछे पुरुषों को आकृष्ट करने और उन्हें अपने मोहपाश में बांधे रखने का मोह ज्यादा होता है। दुनिया भर में बाजारवाद व प्रचारतन्त्र ने अपनी पकड़ तेजी से बढ़ाई है। मनोविज्ञान मानता है कि निरंतर दिखाये/सुनाये जाने वाले विचार मन में गहरे छाप छोड़ते हैं। अखबारों, पत्रिकाओं, टेलीविजन के स्क्रीन पर निरंतर गोरी, चमकदार, दागहीन त्वचा के विज्ञापन हमारी अंतर्चेतना पर छाप बनाते रहते हैं। पुरुषों को आकर्षित करने में सौन्दर्य प्रसाधन महारथी साबित आते हैं। स्त्री इस जाल में आसानी से उलझ जाती है। वह जो नहीं है, वही नजर आने की लालसा में विचारहीनता के साथ पेश आती रहती है। सुपर मॉडल नाओमी कैम्पबेल, मीडिया मुगल ओपरा विन्फ्रे टेनिस स्टार सेरेना विलियम ने तमामेत सुन्दरियों को पछाड़ कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, इन्होंने सौन्दर्य के नये प्रतिमान गढ़ने में भी सफलता पायी। लैंकिग विभेद, नस्लवादी उपेक्षा, यौन प्रताड़ना और काया को लेकर किये गये खतरनाक किस्म के तंजों को दरकिनार करते हुए, नाओमी, ओपरा और सेरेना ने अपने तई सौन्दर्य की इबारतें रचीं। हालांकि मायावती का कद इतना ऊंचा हो चुका है, जहां इस तरह की वाहियात टिप्पणी का उनकी शख्सियत पर कोई विपरीत असर नहीं होना है। पर इस बहाने जरूरत उस सोच को खारिज करने की है, जिसने स्त्री को मानसिक गुलामी में कैद रखा है। सौन्दर्य के पैमाने अब स्त्री को स्वयं गढ़ने होंगे। जो उसकी मेधा, प्रतिभा और प्रखरता के आईने बन सकें।

सार-समाचार

महाराष्ट्र: क्लास टीचर के हाथ Love लेटर लगने पर छात्रा को पड़ी डांट, फिर...

औरंगाबाद. आजकल के बच्चों में इश्क और मोहब्बत का क्रेज काफी तेजी से चल रहा है. सोशल मीडिया के युग में बच्चे प्यार करने के लिए न तो समझदारी देख रहे हैं और न ही परिवार के लोगों के बारे में सोचते हैं. कम उम्र में प्यार का फायदा तो नहीं होता है बल्कि इसके कई सारे दुष्परिणाम भी हैं. कम उम्र में प्यार का एक ऐसा ही किस्सा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में देखने को मिला है. जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को खत लिखकर अपनी बात कहनी चाहिए.

क्लास टीचर के हाथ लगा लव लैटर

प्रेमी के हाथ से वो खत प्रेमिका के हाथ में ना जाकर उनके क्लास टीचर के हाथों में चला गया. इसके बाद क्लास टीचर ने दोनों को सबके सामने

डांट लगाई और दोनों बच्चों के अभिभावकों को स्कूल में बुलाया. इसके बाद दोनों बच्चों की सबके डांट लगाई और कहा कि अगर दोबारा कुछ ऐसा वो करते हैं तो अच्छा नहीं होगा.

घर पहुंचते ही छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

छात्रा ने घर पहुंचते ही खुदकुशी कर ली है. क्लास टीचर की डांट के बाद पंढरपूर में एक नादान छात्रा नें खुद को अपमानित महसूस किया और फांसी लगाकर आत्महत्या की. यह पत्र किसी अंजान शक्स ने भेजा था. छात्रा के पिता बताते है की स्कूल से उन्हें फोन आया था. वह जब स्कूल पहुंचे तो लडकी रो रही थी. क्लास टीचर्स ने कहा की लडकी के पास प्रेमपत्र मिला है. लड़की बार बार कहती रही की ना तो उसका कोई प्रेमी है और ना ही यह प्रेम पत्र किसी ने लिखा है यह पता है. लडकी को समझा बुझाकर घर लेकर आए. तो वह तनाव में दिख रही थी. शाम को कोई घर पर नहीं था. तो उसने खुद को फांसी लगा दी.

छात्रा की मौत के बाद गांववालों ने पढरपूर के वाखरी पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया. उस आशिक को पकड़ने की मांग की गई जिसने छात्रा को प्रेमपत्र लिखा है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

गुरुग्राम में ढही चार मंजिला इमारत, मलबे में 8 लोगों के दबे होने की आशंका

नई दिल्ली. गुरुग्राम के उलावास इलाके में आज सुबह चार मंजिला इमारत गिर गई. बिल्डिंग के मलबे में पांच से ज्यादा लोग दबे हुए हैं. मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए प्रयास जारी है. इमारत के ढहने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में काम चल रहा था. मजदूर अपने काम में लगे हुए थी कि इमारत अचानक गिर गई. इमारत गिरने के बाद मलबे में फंसे मजदूरों की चीख पुखार सुनने के बाद लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया है.

बचाव कार्य में जुटे हैं कर्मचारी

मलबे में से दबे लोगों को निकालने वाले कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ. एक अधिकारी ने बताया कि जिस जगह पर यह हादसा हुए है वह साइबर हब से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की तीन टीमें गाजियाबाद और द्वारका बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी हादसों की संख्या

उल्लेखनीय है कि पिछले एक साल में दिल्ली-एनसीआर में इमारतों के ढहने का सिलसिला जारी है. ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में हुए हादसे के बाद ऐसी घटनाओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है.

आतंकवाद छोड़कर देश के लिए शहीद होने वाले लांस नायक वानी को मिलेगा अशोक चक्र

शहीद लांस नायक को आतंकियों के खिलाफ वीरता से लड़ने के लिए दो बार सैन्य पदक भी मिल चुका है.

नई दिल्ली : जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का रास्ता छोड़कर भारतीय सेना में शामिल हुए शहीद लांस नायक नजीर अहमद वानी को इस साल मरणोपरांत अशोक चक्र के लिए चुना गया है. वह पिछले साल नवंबर में शोपियां में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे. उस दौरान सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था. बता दें कि अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है. शहीद लांसनायक को आतंकियों के खिलाफ वीरता से लड़ने के लिए दो बार सैन्य पदक भी मिल चुका है.

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जान गंवाने वाले लांस नायक नजीर अहमद वानी की कहानी दिलचस्प है. नजीर अहमद वानी पहले आतंकवादी थे, लेकिन जब उन्हें इस बात का अहसास हुआ तो उन्होंने देश विरोधी ताकतों से नाता तोड़ दिया. इसके बाद वह भारतीय सेना में शामिल होकर राष्ट्र सेवा में जुट गए. अधिकारियों के अनुसार 38 वर्षीय वानी कुलगाम के अश्मुजी के रहने वाले थे. वह 25 नवंबर को भीषण मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे. शुरू में आतंकी रहे वानी बाद में हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौट आए थे. वह 2004 में सेना में शामिल हुए थे. अधिकारियों ने बताया कि वानी दक्षिण कश्मीर में कई आतंकवाद रोधी अभियानों में शामिल रहे. जिस मुठभेड़ में वह शहीद हुए, उस समय वह 34 राष्ट्रीय रायफल्स का हिस्सा थे. इसके अलावा वह जम्मू और कश्मीर लाइट इंफैंट्री रेजीमेंट में भी रहे थे.

जम्मू-कश्मीर के चेकी अश्मुजी गांव के रहने वाले शहीद लांसनायक नजीर वानी के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. नवंबर के आखिर में शोपियां में हुई मुठभेड़ में वह शहीद हुए थे. उनके सुपुर्द-ए-खाक के समय सेना के बड़े अफसर भी शामिल हुए थे. शहीद के पिता इस दौरान अत्यधिक दुखी थे. बेटे को खो देने का दुख उनकी आंखों से आंसू के रूप में बाहर आ रहा था.एक सैन्य अफसर ने उनके पास पहुंचकर उन्हें गले लगा लिया था. उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया था. उनको गले लगाने की तस्वीर सेना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी, जो काफी भावुक कर रही थी. इसमें सेना ने शहीद के पिता को ढांढस बंधाते हुए लिखा 'आप अकेले नहीं है.' वानी के सुपुर्द-ए-खाक में 500 से 600 ग्रामीण मौजूद थे. वानी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी.

इंजीनियरिंग छात्र ने बनाई कई खूबियों वाली EVM, छेड़छाड़ ना हो सकने का किया दावा

छात्र का दावा है कि पहले से ही मौजूद EVM में इस टेक्नोलॉजी को फिंगर प्रिंट टेक्नोलॉजी के साथ मैच किया जाएगा.

कोलकाता : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल हमेशा से ही निशाना साधते रहे हैं. 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही इसपर सवाल उठाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है. लेकिन अब कोलकाता के एक इंजीनियरिंग छात्र ने कई खूबियों वाली ईवीएम बनाने का दावा किया है. यहां के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के छात्र राकेश शील ने दावा किया है कि उसकी बनाई मॉडीफाइड ईवीएम से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है.

राकेश शील तृतीय वर्ष का इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का छात्र है. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की तरफ से कोलकाता के साल्ट लेक सेक्टर ङ्क में एक वर्कशॉप और प्रदर्शनी लगाई गई, जो 25 जनवरी तक चलेगी. इसी में इस मॉडीफाइड ईवीएम का प्रदर्शन किया गया है. इसे बनाने वाले राकेश का दावा है कि इससे मतदाताओं के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी. लोग अपना वोट खुद दे पाएंगे. कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी और का वोट नहीं दे पाएगा.

छात्र का दावा है कि पहले से ही मौजूद श्वङ्कारूमें इस टेक्नोलॉजी को फिंगर प्रिंट टेक्नोलॉजी के साथ मैच किया जाएगा. यानी कि मशीन में वोट देने के पहले आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और जब आपका फिंगर प्रिंट दर्ज हो जाएगा, उसके बाद ही आप EVM का बटन दबा पाएंगे, इसके बिना ऐसा नहीं हो पाएगा. उस मशीन के पास ही नंबर या विभिन्न राजनैतिक दलों के चुनाव चिह्न भी मौजूद रहेंगे. लोग इन्हीं को देखकर बटन दबा सकेंगे.

एक बार वोट डालने के बाद अगर कोई व्यक्ति दोबारा वोट डालने पहुंचता है तो तुरंत पकड़ा जाएगा. क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट पहले से ही उस मशीन में दर्ज हो चुके होंगे. यह प्रक्रिया आधार कार्ड के साथ भी जुड़ी रहेगी. छात्र का दावा है कि मतदाता की किसी भी तरह की निजी सूचना लीक नहीं होगी. क ?योंकि मतगणना के ठीक पहले पूरा फिंगरप्रिंट डाटा डिलीट हो जाएगा, जिसके बाद ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी.

दिल्ली : जोरदार टक्कर के बाद 2 कारों में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले

नई दिल्ली : दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बुधवार शाम दिलशाद गार्डन से जाती हुई दो गाड़ियों में आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां आग की भयंकर लपटों में घिर गईं. दोनों गाड़ियों में बैठे 5 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए.

दरअसल घटना बुधवार करीब शाम 7 बजे हुई. जब एक फोर्ड इकोस्पोर्ट्स एसयूवी तेज रफ्तार से आनंद विहार से विवेक विहार की तरफ जा रही थी. इसी दौरान स्पीड तेज होने की वजह से गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया और डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी रोड पर आ गई और एक मारुति ओमनी से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई. इसकी चपेट में दोनों गाड़ियों में सवार पांचों लोग आ गए, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए.

टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई. इस आग में झुलसकर ओमनी वैन सवार एक शख्स की वहीं जलकर मौत हो गई. जबकि लोगों ने किसी तरह दोनों गाड़ियों से 4 लोगों को घायल हालात में बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां 2 और लोगों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक मरने वालों में मुस्तफाबाद के शमशाद, अब्दुल और गर्व सहगल हैं. शमशाद और अब्दुल ओमनी वैन में सवार थे जबकि गर्व इको स्पोर्ट्स में था.

9 घंटे से ज्यादा वक्त तक हुई सर्जरी, डॉक्टरों ने पैर का सबसे बड़ा ट्यूमर निकाला

नई दिल्ली: दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में नौ घंटे तक चले मैराथन ऑपरेशन के बाद 18 वर्षीय युवक की जांघ से 37 सेंटीमीटर लंबा एक विशाल ट्यूमर निकाला गया, जिससे उसे नया जीवन मिला. डॉक्टरों ने बुधवार को यह जानकारी दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह ट्यूमर पैर का अब तक का सबसे बड़ा ट्यूमर है.

उन्होंने कहा कि प्रवीण कुमार गुप्ता को 26 दिसंबर, 2018 को सर गंगा राम अस्पताल में आर्थोपेडिक्स विभाग में भर्ती कराया गया था लेकिन यहां से पहले उन्होंने कई अस्पतालों में जांच कराई थी लेकिन सभी जगह उनका पैर काटे जाने की ही सलाह दी गई थी.

अस्पताल के एक प्रवक्ता ने बताया कि जांच से पता चला कि उसकी जांघ में 37 सेंटीमीटर लंबा 18 सेमी चौड़ा और 12 सेमी मोटा एक विशाल ट्यूमर था, जो कूल्हे और जांघ के पूरे पिछले हिस्से को प्रभावित कर रहा था. लेकिन इस ऑपरेशन के साथ डॉक्टरों ने न केवल प्रवीण का ट्यूमर निकाला बल्कि उसके पैर को काटे जाने से भी बचा लिया. डॉक्टरों के मुताबिक यह पैर से निकाला गया सबसे बड़ा ट्यूमर है और इसे निकालने के लिए मात्र एक बोटल खून की आवश्यता पड़ी.

2012 से पीड़ित थे प्रवीण

जानकारी के मुताबिक प्रवीण के ट्यूमर प्रभावित हिस्से में 2012 में ही सूजन दिखाई देने लगी थी और वक्त के साथ यह ट्यूमर बढ़ता चला गया. इस सर्जरी के लिए आर्थोपेडिक्स, वैस्कुलर सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और एनेस्थिसियोलॉजी विभाग के चिकित्सकों से मदद ली गई.

गणतंत्र दिवस पर इतिहास रचने जा रहीं लेफ्टिनेंट कस्तूरी बोलीं- 'सेना में लैंगिक भेदभाव नहीं'

आर्मी सर्विस कॉर्प्स में लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड में पुरुष सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेंगी.

नई दिल्ली : इस बार 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर महिला सशक्तीकरण की बेहद सशक्त तस्वीर देखने को मिलेगी. 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड में पहली बार कोई महिला पुरुष सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करती दिखेगी. आर्मी सर्विस कॉर्प्स में लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी देश को यह गौरवपूर्ण पल देंगी. इससे पहले लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने सेना दिवस की परेड में भी ऐसा करके महिला सशक्तीकरण की मिसाल पेश की थी.

इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प्स (ASC) की टुकड़ी में 144 पुरुष जवान शामिल होंगे. इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने जा रहीं लेफ्टिनेंट कस्तूरी से हमारे सहयोगी चैनल Wion के संवाददाता सिद्धांत सिब्बल द्वारा की गई बातचीत के कुछ अंश: पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने को लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है ?

– यह मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात की बात है. साथ ही हमारे लिए यह गौरव की बात है. यह आर्मी सर्विस कॉर्प में ऐतिहासिक पल ही होगा कि हमारी टुकड़ी गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा होगी. यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे 2 जूनियर कमीशंड ऑफिसर (जेसीओ) और 144 जवानों के लिए सौभाग्य की बात है. यह हमारे लिए ऐतिहासिक होगा. इससे हम हमेशा के लिए इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाएंगे.**सेना में बतौर महिला आपका अनुभव कैसा है ?**

– मेरा मानना है कि भारतीय सेना में लैंगिक असमानता नाम की कोई भी बात नहीं है. सेना में एक अफसर हमेशा अफसर ही रहता है, जिम्मेदार और सेवा का अधिकार भी समान ही रहता है. हमें सेना की क्षमता की तस्वीर को बड़े प्लेटफार्म पर प्रदर्शित करने का बड़ा मौका मिला है.

क्या पुरानी परंपराएं और रुकावटें दूर हो रही हैं ?

– जी हां, भारतीय समाज में विभिन्न तरह के बदलाव हो रहे हैं. यह सिर्फ सेना में ही नहीं है, बल्कि यह आम जीवन में भी हो रहा है कि महिलाएं अद्भुत कार्य कर रही हैं. मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि हम लगातार बेहतर कर रहे हैं.

देश की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं ?

– मेरा मानना है कि मैं अभी भी खासकर लड़कियों के लिए रोल मॉडल हूं. मैं सभी से यह कहना चाहती हूं कि अपने सपने को जीने के लिए प्रयासरत रहें. बीच में कभी हार ना मानें.

पंजाब:सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, केक काट कर सीएम को याद दिलाया वादा

पंजाब: ना नारेबाजी, न जिंदाबाद मुर्दाबाद, ना ही कोई घेराव एक अलग तरीके का प्रदर्शन जो देखने को मिला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर. जिसमें ठेका कर्मचारी एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर केक काटकर विरोध प्रदर्शन किया. बकायदा केक पर कैप्टन अमरिंदर के उस ट्वीट की फोटो बनवाई गई थी जो ट्वीट कैप्टन अमरिंदर ने 24 जनवरी 2017 को किया था.

2 साल पहले किए गए ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा था कि सरकार बनने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा की ठेका कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाए. साथ ही किसी भी नए ठेका कर्मचारी की भर्ती ना हो. अब ठेका कर्मचारी का आरोप है कि पंजाब में मुख्यमंत्री बन चुके हैं उसके बाद भी कैप्टन अपना वादा भूल गए इसीलिए वह सीएम साहब को केक खिलाकर उनका वादा याद दिलाने आए हैं.

दरअसल कैप्टन अमरिंदर आज से ठीक 2 साल पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया था कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो ठेका कर्मचारियों को पक्का करने के अलावा ठेका कर्मचारियों पर कोई नई भर्ती नहीं होगी.

मेनिफेस्टो के अलावा एक बड़ा वादा था जिस वादे के नाम पर कैप्टन अमरिंदर ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन ठेका कर्मचारी एक्शन कमेटी का कहना है कि 2 साल हो गए हैं उनके साथ लोग मिलते हैं, बातें करते हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ इसीलिए उनको यह कदम उठाना पड़ा है,

ठेका कर्मचारी एक्शन कमेटी केक लेकर आई और मुख्यमंत्री आवास की तरफ जब जाने लगे तो उसे पहले ही उनको रोक लिया गया. इसके बाद ठेका कर्मचारी एक्शन कमेटी ने वहीं पर केक काटकर अपना विरोध जताया. हालांकि बिना केक के उनको सीएम आवास पर मिलने का वक्त दे दिया गया था, लेकिन ठेका कर्मचारी एक्शन कमेटी बिना केक के सीएम आवास मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गए.

सूरत। सुरत महानगर पालिका के डे.इ. वी.के परमार से परेशान लोगों का कहना हैं, की अगर हम अपना धंधा (लारी-गल्ले) नहीं लगाएंगे तो हमे भीख मांगनी पडेगी, सुरत महानगर पालिका के अधिकारीयों का पूरा ध्यान सिर्फ लारी-गल्ला वाले के पीछे ही पड़ा हैं, जितने रकम का मॉल-समान लाते हैं उससे ज्यादा रकम तो दण्ड के रूप में भरना पड़ता है, वह भी काफी परेशानी करने के बाद में क्या ज़ोनल ऑफिसर ,और मुनिसिपल कमिश्नर को इस बारे में जानकारी हैं, शहर के सारे नगर सेवक क्या अंजान हैं ? या मिलीभगत से होता ?

सूरत। गुरुवार को फोस्टा तथा मिलेनियम टेक्षटाइल मार्केट एसोशिएशन द्वारा शाम 5 बजे मिलेनियम टेक्षटाइल मार्केट के बोर्ड रूम में जोईंट कमिशनर आफ इनकम टैक्स श्री जे.के. चंदनानी, आयकर अधिकारी बोर्ड नरेन्द्रन तथा आयकर अधिकारी अजित बनिक के साथ ओपन हाउस सेमिनार का आयोजन किया गया। आए हुए फोस्टा तथा मिलेनियम मार्केट के पदाधिकारियों तथा सभी मार्केट के पदाधिकारियों ने जोइंट कमिश्रन से अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा विचारण की तथा चंदनानी ने सभी की समस्याओं को सूना, सभी समस्याओं को सुन्ने के बाद चंदनानी ने समस्याओं का समाधान किया तथा उन्होंने ने यह भी कहा कि व्यापारीवर्ग को कोई भी समस्या हो तो वह निसंकोच बिना किसी गभराहट के हमसे आकर संपर्क कर सकते है, उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है। आज की ओपन हाउस सोमिनार में फोस्टा से रंगनाथ शारड़ा, मिलेनियम मार्केट से गुरुमुख कुंगवानी, सुरेन्द्र भंसाली एवं एसोशिएशन के पदाधिकारी व मार्केटों के व्यापारी बड़ीं संख्या में उपस्थित रहे।

सूरत। सामाजिक न्याय और अधिकरिता मंत्री इश्वरभाई परमार ने बाबेन गाम में 12 लाख रुपए के खर्च से माह्यवंशी महोल्ला से भूरी सिमरक तक डामर रोड़ बनाने के लिए भूमि पुजन किया।

सूरत। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा आयोजित अभिभावक दिव्स के उपलक्ष्य में कार्यक्रम उधना के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित किया गया जिसमें भारी संख्या में स्कूल के बच्चे तथा उनके माता पिता ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जिसमें नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष उधना विधानसभा के विधायक और कार्पोरेटर सहित स्कूल के टीचर्स मौजुद रहे।

लोकप्रिय गायिका किंजल दवे को राहत मिली

किंजल दवे को चार चार बंगड़ी गीत गाने की मंजुरी

गुजरात हाईकोर्ट ने कोमर्शियल कोर्ट के फैसले को अस्वीकार किया : किंजल के समर्थको में खुशी दिखी

अहमदाबाद । लोकप्रिय गायिका किंजल दवे को चार चार बंगडी वाले गीत को गाने की मंजुरी मिल गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में किंजल दवे को गीत गाने की परवानगी दे दी है । हाईकोर्ट ने कोमर्शियल कोर्ट की ओर से लागू किए गए स्टे को दुर सरते हुए किंजल दवे को बड़ी राहत दे दी है । गीत के खिलाफ हमेशा के लिए स्टे के मामले में याचिका पर सुनवाई करने को कोमर्शियल कोर्ट को कहा गया है । गुजरात हाईकोर्ट ने किंजल को बड़ी राहत दे दी है । हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचने के बाद सुनवाई पर सभी लोगों की नजर लगी हुई थी । गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में कुछ और भी निर्देश जारी किये है । केस की पुरी जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि गायिका किंजल दवे को कोमर्शियल कोर्ट ने कोपीराइट केस के उल्लंघन के मामले में लोकप्रियता जगा चुके चार चार बंगडी वाले गीत गाने की मंजुरी नहीं दी थी । ४ जनवरी के दिन इस तरह का आदेश जारी किया गया था । कोपीराइट के केस में कोमर्शियल कोर्ट ने दो दिन पहले ही एक दिन के लिए स्टे का भी आदेश दिया था । जिसके चलते किंजल दवे ने कोपीराइट के केस और कोमर्शियल कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी । इस रीट याचिका पर कल दोनों पक्षो की ओर से सुनवाई की गई । दलीलबाजी भी की गई । इसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला अनामत रख लिया था । आज खुली अदालत में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कोमर्शियल कोर्ट के स्टे के फैसले को अस्वीकार कर दिया । किंजल दवे की ओर से हाईकोर्ट में की गई याचिका में एडवोकेट हर्षित तोलीया और जयदीप वाघेला की ओर से दलीलबाजी की गई थी । उन्होंने बताया कि किंजल दवे के खिलाफ बिनजरुरी आदेश जारी किया गया है । किंजल दवे के वकीलो ने कोमर्शिय कोर्ट के फैसले को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी । इसके अलावा किंजल दवे को गीत गाने की मंजुरी दीए जाने की भी मांग की थी।

भानुशाली की हत्या छबील पटेल व मनीषा गोस्वामी ने करवाई

भानुशाली हत्या केस में दो और गिरफ्तार : बड़ा खुलासा हुआ

कच्छ के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की हत्या कराने के लिए छबील पटेल व मनिषा ने पुना के शार्पशूटर को सुपारी दी थी : बड़ा खुलासा हुआ

अहमदाबाद । सनसनीखेज जयंती भानुशाली हत्या प्रकरण में आज बड़ा खुलासा हुआ । इस मामले में दो और की गिरफ्तारी हुई है । गुजरात के अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशिक अजय तोमर ने बताया कि निजी दुश्मनी की चले जयंती भानुशाली की हत्या की गई । अहमदाबाद, गुजरात भाजपा के दिग्गज नेता व कच्छ के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की हत्या भाजपा के ही नेता छबील पटेल व मनीषा गोस्वामी ने करवाई थी । दोनों इसके लिए पुणे के शार्पशूटर को सुपारी दी थी । गुजरात पुलिस ने बताया कि हत्या के तीन दिन पहले छबील पटेल विदेश भाग गए और मनीषा गोस्वामी भी फरार है। इस हत्याकांड में छबील पटेल के दो सहयोगी राहुल व वसंत पटेल को गिरफ्तार किया गया है । बाकी सभी आरोपितों की तलाश की जा रही है। कच्छ की अबडासा सीट से वर्ष २००७-१२ तक विधायक रहे भानुशाली गत सात जनवरी को सयाजीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच एच-१ में भुज से अहमदाबाद आ रहे थे। इसी दौरान रात १२.५५ बजे भचाउ से समिखयाली रेलवे स्टेशन के बीच उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । घटना के बाद गुजरात सरकार ने एसआइडी का गठन किया था तथा गुजरात एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीमें भी जांच में जुटी थी ।

गुजरात के अतिरिक्तपुलिस महानिदेशक अजय तोमर ने गुरुवार को बताया कि निजी दुश्मनी के चलते जयंती भानुशाली की हत्या की गई । भाजपा के नेता व पूर्व विधायक छबील पटेल और जयंती भानुशाली पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली मनीषा गोस्वामी मुख्य आरोपित है । मनीषा गोस्वामी के खिलाफ जयंती भानुशाली के भतीजे सुनील भानुशाली नरोडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी । पुलिस ने उसे १० जून को जेल में बंद कर दिया था । छबील पटेल की मदद से तीन अगस्त के दिन मनीषा गोस्वामी जेल बाहर आई थी । जिसके बाद दोनों ने मिलकर जयंती भानुशाली की हत्या का प्लान बनाया । दोनों ने पूणे के सुरजित भाउ गैंग का संपर्क कर हत्या की सुपारी दी थी । शार्प शूटर सुरजीत भाउ ,शंशिकांत कांबेल और शेख असरफ ने इस हत्या को अंजाम दिया । तीनों हत्या के एक हसे पहले से ही कच्छ में स्थित छबील पटेल के फार्म हाउस में ठहरे थे । यहां हत्या का प्लान बनाया गया और जयंती भानुशाली की गतिविधियों नजर रखी गई थी ।

पुलिस ने बताया कि भानुशाली की हत्या के छह दिन पहले ही छबील पटेल विदेश भाग गया था, जबकि मनीषा गोस्वामी और छबील के दो सहयोगी राहुल और वसंत पटेल ने फार्म हाउस में तीनों शार्पशूटरों को तमाम प्रकार की सुविधा पहुंचाई थी । जयंती भानुशाली के भुज से अहमदाबाद ट्रेन से जाने की पूरी जानकारी हासिल करने के बाद मनीषा भी फरार हो गई । पुलिस ने बताया कि रात के सात जनवरी को ११ बजे के करीब भुज से सयाजीनगरी ट्रेन में सवार हुए जयंती भानुशाली की हत्या करने के लिए शार्पशूटर शशिकांत और शेख असरफ रात १२ बजे के पास भचाऊ रेलवे स्टेशन से एसी कोच में चढ़े थे। करीब १२.५५ बजे दोनों ने जयंती भानुशाली के केबिन का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही भानुशाली ने दरवाजा खोला दोनों उनके आंख और छाती पर गोली मार दी । इसके बाद आरोपितों ने उनका एक मोबाइल और बैग लेकर ट्रेन का चैन पुलिंग कर कार में राधनपुर हाईवे से होकर पूणे चले गए। शार्पशूटरों को सुविधा मुहैया करवाने वाले छबील पटेल के सहयोगी वसंत पटेल और राहुल पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)**